भारतीय रुपये का अंतरराष्ट्रीयकरण और रुपये में इनव्रॉइस का प्रभाव

डॉ. बिबेकानंद पांडा*

हीरालाल करनावट**

भारतीय रुपये में इनव्रॉइस यानी भारत और उसके व्यापारिक भागीदारों के बीच हुए व्यापारिक लेनदेनों के लिए भुगतान की ऐसी व्यवस्था, जिसमें दोनों देश अपनी-अपनी इनव्रॉइस भारतीय रुपये में बनाते हैं और अपने व्यापार के लिए द्विपक्षीय आधार पर भुगतान भारतीय रुपए में करते हैं। भारतीय रुपये में इनव्रॉइस की इस व्यवस्था से लेनदेन की लागत में कमी आने की आशा है, क्योंकि अधिकांश लेनदेन जोखिम रहित हो जाएंगे। इससे भारत का निर्यात और वैश्विक व्यापार बढ़ने की भी आशा है। साथ ही, भारत की मुद्रा में रुचि रखने वाले वैश्विक व्यापार समुदाय को इस कदम से संबल मिलेगा। भारतीय रुपये के अंतरराष्ट्रीयकरण का पथ प्रशस्त करने के अभिप्राय से यह कदम उठाया गया है।

सीमा पार के लेनदेनों के लिए भारतीय रुपये का प्रयोग बढ़ाने की प्रक्रिया को ही रुपये का अंतरराष्ट्रीयकरण कहा जाता है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा वह होती है, जिसे अनिवासी अपने विदेशी लेनदेनों के लिए मुक्त रूप से प्रयोग कर सकें। रुपये का अंतरराष्ट्रीयकरण भारतीय मुद्रा और अर्थव्यवस्था में बढ़ते भरोसे का प्रतीक है। रूपये को अंररराष्ट्रीयकरण के कारण विदेशी मुद्राओं में आने वाले उतार-चढाव के द्वारा व्यवसाय में होने वाले नुकसान से बचा जा सकेगा। मुद्रा के उतार-चढ़ाव से बचाव होने पर व्यवसाय की लागत कम हो जाएगी। एक अन्य लाभ यह होगा कि भारतीय रिज़र्व बैंक के लिए विदेशी मुद्रा का बड़ा भंडार रखने की जरूरत कम हो जाएगी। इस भंडार को बनाए रखना एक खर्चीला काम है। सबसे बढ़कर, भारत भुगतान संतुलन के संकटों से सुरक्षित हो जाएगा क्योंकि अपने बाह्य घाटे के लिए वह अपनी मुद्रा में भुगतान कर सकेगा।

किसी भी मुद्रा को अंतरराष्ट्रीय मुद्रा बनने के लिए पहली आवश्यकता है कि व्यावसायिक बीजक (invoice) बनाने में उसका अधिक से अधिक प्रयोग हो। बीआइएस (BIS) के त्रिवार्षिक सर्वेक्षण 2022 के अनुसार विदेशी-मुद्रा-बाजार-लेनदेन (दैनिक औसत) में सबसे बड़ा हिस्सा अमेरिकी डॉलर का है। वैश्विक लेनदेन में इसका अंश 88 प्रतिशत है। इसके बाद यूरो (31 प्रतिशत), जापानी येन (17 प्रतिशत) तथा पौंड स्टर्लिंग (13 प्रतिशत) का स्थान है, जबकि भारतीय रुपये की भागीदारी केवल 2 प्रतिशत है। चूँकि हर लेनदेन में दो अलग-अलग मुद्राएँ शामिल होती हैं, इसलिए हर देश के अंश का योग 200 प्रतिशत हो जाता है।

इसी प्रकार, 149 रिपोर्टरों द्वारा तैयार 'आइएमएफ कॉफर' आँकड़ों के अनुसार वैश्विक विदेशी मुद्रा भंडार में अमेरिकी डॉलर का हिस्सा 2022 की चौथी तिमाही में 58.4 प्रतिशत था। इसके बाद यूरो (20.5 प्रतिशत), जापानी येन (5.5 प्रतिशत), पॉउंड स्टर्लिंग (5.0 प्रतिशत), चीनी रेन्मिन्बि (2.7 प्रतिशत), कनाडाई डॉलर (2.4 प्रतिशत), ऑस्ट्रेलियाई डॉलर (2.0 प्रतिशत) तथा स्विस फ्रैंक (0.2 प्रतिशत) का स्थान था।

चार्ट : सरकारी भंडारों में विदेशी मुद्राओं की स्थिति

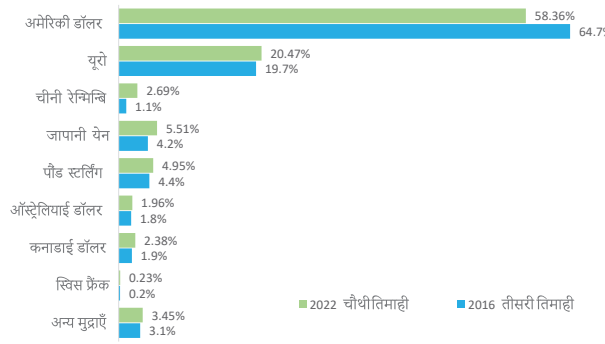

स्रोत : अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आइएमएफ)।

नोट : अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने चीनी रेन्मिन्बि का मूल्य 2016 की चौथी तिमाही से प्रकाशित करना प्रारंभ किया। इसलिए चीनी रेन्मिन्बि के आँकड़े 2016 की चौथी तिमाही के हैं।

रुपये में इनवॉइस – हाल का घटनाक्रम

भारतीय रुपये में अंतरराष्ट्रीय भुगतान की संरचना का महत्व इस दृष्टि से बढ़ जाता है कि अमेरिकी फेडरल रिज़र्व द्वारा नीतिगत दरों को आक्रामक रूप से बढ़ा दिए जाने से अमेरिकी

*सहायक महाप्रबंधक (अर्थशास्त्री), भारतीय स्टेट बैंक, हैदराबाद।
**सेवानिवृत्त सहायक महाप्रबंधक (राजभाषा), भारतीय स्टेट बैंक, अहमदाबाद।

डॉलर जिस ऊँचाई पर पहुँच गया है, वह पिछले कई दशकों में सबसे अधिक है। इसी कारण उभरती बाजार अर्थव्यवस्था वाले (ईएमई) देशों की मुद्राओं का अवमूल्यन हुआ है, जिनमें भारतीय रुपया भी शामिल है। भारतीय रुपये का मुद्रागत मूल्य बाजार द्वारा निर्धारित होता है, क्योंकि भारतीय रिज़र्व बैंक अत्यधिक अस्थिरता की स्थिति में ही विदेशी मुद्रा बाजार में हस्तक्षेप करता है। वर्ष 2022 के दौरान भारतीय रुपये का मूल्य 11 प्रतिशत से अधिक गिर गया, जबकि अमेरिकी डॉलर सूचकांक के अनुसार अमेरिकी डॉलर का मूल्य 6 प्रतिशत से अधिक बढ़ गया। भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्र से पूर्व भूटान, नेपाल आदि गिने-चुने देशों के साथ ही भारतीय रुपये में व्यापार संभव था।

इस संरचना में चालू खाते से संबंधित व्यापारिक प्राप्तियों और भुगतान में विदेशी मुद्रा की, विशेषकर अमेरिकी डॉलर की, निवल माँग को काफी कम करने की क्षमता है। साथ ही, विदेशी व्यापार में भारतीय रुपये के उपयोग से भारतीय प्रतिष्ठानों में मुद्रागत जोखिम कम हो जाएगा। मुद्रा के भाव में उतार-चढ़ाव से बचाव होने पर न केवल व्यवसाय की लागत कम हो जाएगी, बल्कि व्यवसाय में अधिक वृद्धि होगी और भारतीय प्रतिष्ठानों को विदेश में फलने-फूलने के अधिक अवसर प्राप्त होंगे। इससे विदेशी मुद्रा भंडार की आवश्यकता और विदेशी मुद्रा पर निर्भरता कम हो जाएगी, परिणामस्वरुप भारतीय अर्थव्यवस्था पर बाहरी झटकों का असर कम होगा। मुद्रागत जोखिम कम होने से आगत पूंजी के वापस जाने की अप्रिय स्थिति में भी कमी आएगी। वर्ष 2013 का 'टैपर टेन्ट्रम' घटनाक्रम और हाल ही में अधिकांश ईएमई मुद्राओं में जारी अस्थिरता मुद्रागत जोखिम के उदारहण हैं। रुपये में व्यापार की प्रक्रिया भारत को भुगतान संतुलन के संकट से भी बचाएगी, क्योंकि भारत अपने विदेशी व्यापार घाटे के लिए अपनी ही मुद्रा से भुगतान कर सकेगा। इतना ही नहीं, इससे भारतीय निर्यातकों को विदेशी ग्राहकों से भारतीय रूपये में अग्रिम भुगतान लेने में भी मदद मिलेगी और एक बार भारतीय रुपये में निपटान की संरचना में गति आने पर आने वाले समय में भारतीय रुपया अंतरराष्ट्रीय मुद्रा के रूप में आगे बढ़ सकता है।

भारतीय रुपये में निपटान के विषय में भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुदेश

भारत की बैंकिंग प्रणाली के नियामक भारतीय रिज़र्व बैंक ने जुलाई 2022 में एक परिपत्र जारी कर आयात-निर्यात के लिए इनवॉइस, भुगतान तथा निपटान भारतीय रुपये में करने हेतु अतिरिक्त करार करने की अनुमति दी है। वैश्विक व्यापार, विशेषकर भारत से निर्यात बढ़ाने और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा के रूप में भारतीय रुपये के प्रति वैश्विक व्यापार समुदाय की बढ़ती रुचि को पुष्ट करने के लिए यह कदम उठाया गया है। आयात-निर्यात दोनों के लिए भारतीय रुपये में बीजक बनाना, व्यापार करने वाले देशों की आपसी मुद्राओं की बाजार-निर्धारित विनिमय दरें और विशेष रुपया वोस्त्रो खाता (Special Rupee Vostro Account or SRVA) के माध्यम से निपटान आदि बातें इस संरचना में शामिल हैं।

वोस्त्रो खाता यानी ऐसा खाता, जो प्रतिनिधि बैंक द्वारा अन्य बैंक की ओर से रखा जाता है। ये खाते प्रतिनिधि बैंकिंग का अनिवार्य पहलू हैं, जिसमें निधियाँ धारित करने वाला बैंक अभिरक्षक के रूप में कार्य करता है या विदेशी बैंक के खाते का प्रबंध करता है। विशेष रुपया वोस्त्रो खाता (एसआरवीए) नए प्रकार की व्यापारिक व्यवस्था है। अंतरराष्ट्रीय व्यापार का निपटान भारतीय रुपये में करने के लिए रिज़र्व बैंक ने इसकी घोषणा की है। व्यापारिक सौदों का निपटान करने के लिए अधिकृत बैंक को व्यापारिक भागीदार देश के बैंकों में एसआरवी खाता खोलना और रखना होगा। इसके अनुमोदन की निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार एसआरवी खाता खोलने के लिए व्यापारिक भागीदार देशों के बैंकरों को भारत में कार्यरत प्राधिकृत बैंकों के पास जाना होगा। वे इसके लिए रिज़र्व बैंक से अनुमोदन प्राप्त करेंगे। अनुमोदन में इस व्यवस्था का ब्योरा दिया जाएगा। जिस बैंक में एसआरवी खाता होगा, उस बैंक को सुनिश्चित करना होगा कि प्रतिनिधि बैंक उस देश या क्षेत्रों (jurisdiction) से नहीं है, जिन्हें वित्तीय कार्रवाई कार्यदल (Financial Action Task Force) ने उच्च जोखिमयुक्त और असहयोगी क्षेत्रों की अद्यतन सार्वजनिक सूचना में रखा हो और जिनके विरुद्ध प्रतिबंधक उपाय किए हों।

एसआरवी खाते विदेशी मुद्रा प्रबंधन (जमाराशि) विनियम, 2016 के अंतर्गत पहले से खुले रुपया वोस्त्रो खातों से अलग प्रकार के खाते हैं। भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुसार अंतरराष्ट्रीय व्यापार का भारतीय रुपये में निपटान एक अतिरिक्त व्यवस्था है। यह निपटान की उस वर्तमान व्यवस्था के अतिरिक्त है, जिसमें आसानी से बदली जा सकने वाली मुद्रा का मुक्त रूप से प्रयोग किया जाता है। एसआरवी खाता एक अनुपूरक प्रणाली के रूप में कार्य करता है, जिससे दुर्लभ मुद्रा/मुक्त रूप से प्रत्यावर्तनीय मुद्रा पर निर्भरता बहुत कम हो जाती है।

निपटान की इस व्यवस्था के अंतर्गत (क) भारतीय आयातक अपने आयातों के लिए भारतीय रुपये में भुगतान करेंगे। विदेशी विक्रेता/आपूर्तिकर्ता के साथ जिन वस्तुओं/सेवाओं के आयात

का सौदा किया गया हो, उनकी आपूर्ति की इनवॉइस पर यह राशि भागीदार देश के प्रतिनिधि बैंक के एसआरवी खाते में जमा हो जाएगी। जबकि (ख) इस व्यवस्था के अंतर्गत वस्तुओं और सेवाओं का निर्यात करने वाले भारतीय निर्यातकों को उनके निर्यात की राशि भारतीय रुपयों में चुकाई जाएगी। भागीदार देश का प्रतिनिधि बैंक निर्धारित एसआरवी खाते में शेष राशियों में से यह भुगतान करेगा। भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा तैयार संरचना उन सभी भागीदार देशों पर लागू होगी, जो भारत से भारतीय रुपयों में व्यापार करना चाहते हैं।

एसआरवी खाते में शेष राशि का उपयोग अग्रलिखित कार्यों के लिए किया जा सकता है – (क) परियोजनाओं तथा निवेशों के लिए भुगतान, (ख) निर्यात/आयात अग्रिम प्रवाह प्रबंधन और (ग) सरकारी ट्रेज़री बिलों, सरकारी प्रतिभूतियों आदि में निवेश, जो प्रचलित दिशानिर्देशों तथा निर्धारित सीमाओं में, साथ ही, भारत के विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम और इसी प्रकार के अन्य सांविधिक प्रावधानों के अनुसार हो। इसका एक अतिरिक्त लाभ यह होगा कि एसआरवी खाते में शेष राशि मुक्त रूप से परिवर्तनीय मुद्रा में तथा/अथवा व्यापारिक भागीदार देश की मुद्रा में प्रत्यावर्तित की जा सकेगी। इस प्रत्यावर्तन का आधार होगा संबंधित लेनदेन, जिसके लिए राशि खाते में जमा की गई है। उदाहरण के लिए, एसआरवी खाते से आयात के भुगतान के लिए विदेशी निर्यातक को राशि का अंतरण किसी भी अन्य रुपया वोस्त्रो खाते की तरह मुक्त रूप से परिवर्तनीय मुद्रा में या विदेशी निर्यातक की घरेलू मुद्रा में किया जा सकता है।

भारतीय रुपये में इनवॉइस को बढ़ावा देने के लिए विदेश व्यापार नीति में किए गए संशोधन

अंतरराष्ट्रीय व्यापार निपटान भारतीय रुपये में करने अर्थात् आयात-निर्यात की इनवॉइस, भुगतान, निपटान आदि कार्य रिज़र्व बैंक के जुलाई 2022 के परिपत्र के अनुरूप भारतीय रुपये में करने की अनुमति के लिए महानिदेशक, भारतीय विदेशी व्यापार ने सितंबर 2022 में भारतीय विदेश व्यापार नीति में संशोधन किया। तत्पश्चात नवंबर 2022 में कुछ और परिवर्तन किए गए, परिणामस्वरुप रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुरूप निर्यात लाभ और निर्यात वचनबद्धता की पूर्ति हेतु निर्यात से प्राप्त राशि भारतीय रुपये में प्रदान की जा सके। भारतीय रुपये के अंतरराष्ट्रीयकरण में बढ़ती रुचि को देखते हुए व्यापार नीति में परिवर्तन किए गए हैं, ताकि अंतरराष्ट्रीय व्यापारिक लेनदेन भारतीय रुपयों में आसानी से हो सके। हाल में 31 मार्च 2023, को जारी नई विदेश-व्यापार-नीति भी रुपये के अंतरराष्ट्रीयकरण को प्रोत्साहित करती है।

रुपये में इनवॉइस और भारतीय निर्यात : एक मूल्यांकन

आशा की जाती है कि रुपये में इनवॉइस से लेनदेनों की लागत कम हो जाने से भारत का अंतरराष्ट्रीय व्यापार बढ़ेगा, क्योंकि इस प्रक्रिया से अधिकांश लेनदेन जोखिम रहित हो जाएंगे। इस व्यवस्था से वैश्विक व्यापार भी बढ़ेगा। इसमें भारत से निर्यात पर बल दिया जाएगा। भारत की घरेलू मुद्रा में वैश्विक व्यापार समुदाय की बढ़ती रुचि भी इससे पुष्ट होगी। नई सुविधा से आयातक और निर्यातक दोनों को कीमत में अधिक पारदर्शिता प्राप्त होगी और लागत में बचत की संभावना बढ़ेगी। विदेशी मुद्रा विनिमय की जरूरत न रह जाने से भारतीय रुपये में इनवॉइस प्रस्तुत करते ही निर्यातकों को अधिक शीघ्रता से भुगतान प्राप्त हो जाएगा, लागत में बचत होगी और भुगतान प्रक्रिया में तेजी आएगी।

भारतीय रुपये में माल खरीदने से भारतीय उत्पादों के आयातकों के लिए संभवत: माल की लागत घटेगी, क्योंकि भारतीय कंपनियाँ उत्पादन और प्रशासनिक लागत भारतीय रुपयों में लगाती हैं। भारतीय निर्यातकों के लिए अपने माल की इनवॉइस भारतीय रुपयों में देना और भुगतान भी भारतीय रुपये में प्राप्त करना संभव हो जाएगा। फलस्वरुप भारतीय कंपनियों का अंतरराष्ट्रीय स्तर पर व्यापार बढेगा और उन्हें विक्रय प्रक्रिया में लगने वाली विदेशी मुद्रा के विनिमय से जुड़े जोखिम का प्रबंधन करने में सहायता होगी। आयात की बात करें तो निर्यात की तुलना में भारत का आयात अधिक होने से आयात के लिए रुपये में भुगतान करने से विदेशी मुद्रा का अन्तर्वाह (inflows) बढ़ेगा। रुपये की कीमत में स्थिरता की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम होगा।

यह संरचना उन भागीदार देशों के साथ व्यापार में विशेष लाभप्रद है, जो विभिन्न कारणों से डॉलर (विदेशी मुद्रा) की कमी का सामना कर रहे हैं। नई व्यवस्था से भारत को ऐसे देशों के साथ व्यापार बढ़ाने में मदद मिलेगी। रुपये में इनवॉइस की व्यवस्था से भारतीय आयातक एसआरवी खाते के माध्यम से रुपये में भुगतान करेंगे और निर्यातकों को भी रुपये में भुगतान प्राप्त होगा। रूस, सऊदी अरब, नाइजीरिया और संयुक्त अरब अमीरात जैसे व्यापारिक भागीदारों के साथ रुपये में व्यापार अधिक अनुकूल रहेगा, क्योंकि भारत एक बड़ा आयातक है और भारतीय माल के निर्यात के अवसर काफी अधिक हैं।

तालिका : भारतीय रुपये में निपटान की संभावना वाले देश

देश	2021 में भारत से निर्यात (मिलियन अमेरिकी डॉलर)	2021 में भारत में आयात (मिलियन अमेरिकी डॉलर)	2021 में भारत का व्यापार संतुलन (मिलियन अमेरिकी डॉलर)
इराक	2032.4	26566.1	-24533.7
सऊदी अरब	8245.4	27689.3	-19443.9
संयुक्त अरब अमीरात	25446.6	43070.3	-17623.7
रूस	3334.3	8695.0	-5360.8
नाइजीरिया	4523.1	9157.9	-4634.8
गिनी	596.0	3446.7	-2850.7
घाना	1099.2	1588.9	-489.8
पापुआ न्यू गिनी	66.7	325.6	-258.9
लीबिया	207.9	368.5	-160.6
कैमरनून	390.8	481.3	-90.5
म्याँमार	839.0	798.8	40.3
जिम्बाब्वे	188.9	5.7	183.1
जांबिया	334.8	130.9	203.9
भूटान	867.7	343.9	523.9
मालदीव	591.8	50.7	541.1
मॉरीशस	745.5	66.7	678.8
सूडान	1006.1	258.8	747.3
ईरान	1284.0	408.7	875.3
श्रीलंका	4799.8	979.8	3819.9
नेपाल	9189.9	1317.7	7872.1
बांग्लादेश	14092.7	1764.1	12328.6

स्रोत : आइटीसी ट्रेड मैप

रुपये में इनवॉइस बनाने में हो रही प्रगति

रूस-युक्रेन युद्ध के कारण पश्चिमी देशों द्वारा रूस पर लगाए गए प्रतिबंधों के बाद भारत रुपये में व्यापार को बढ़ावा देने का प्रयत्न कर रहा है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय तथा भारतीय रिज़र्व बैंक के संयुक्त प्रयासों से रुपये में इनवॉइस का कार्यक्रम आगे बढ़ रहा है। रूस के अलावा अन्य कई देशों के साथ रुपये में व्यापार करने के बारे में बातचीत काफी आगे बढ़ी है। भारत सरकार रुपये में अंतरराष्ट्रीय व्यापार को आगे बढ़ा रही है, वहीं रिज़र्व बैंक के परिपत्र का उद्देश्य यह है कि वैश्विक व्यापार बढ़े और भारत से निर्यात भी। साथ ही, वैश्विक व्यापार समुदाय की भारतीय रुपये में बढ़ती रुचि को संबल मिले।

प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार रुपये में व्यापार के प्रति रुचि दिखाई दे रही है। केवल छह माह में एसआरवी खातो की संख्या 60 हो गई है, जिससे स्पष्ट होता है कि रुपये में व्यापार की सुविधा प्रदान करने की भारत की नीति सफल हो रही है। अठारह देशों (बोत्सवाना, फिजी, जर्मनी, गयाना, इज़राइल, केन्या, मलेशिया, मॉरीशस, म्याँमार, न्यूज़ीलैंड, ओमान, रूस, सेशल्स, सिंगापुर, श्रीलंका, तंजानिया, युगांडा और यूनाइटेड किंगडम) ने रुपये में विदेश व्यापार के लिए एसआरवी खाते खोले हैं। ये खाते 20 भारतीय बैंकों में खोले गए हैं, जिनमें सरकारी बैंक भी हैं और निजी भी। भारतीय स्टेट बैंक, यूको

बैंक, एचडीएफसी बैंक, यस बैंक, आईडीबीआई बैंक, पंजाब नैशनल बैंक, एक्सिस बैंक, केनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा तथा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया जैसे बैंकों ने विशेष वोस्त्रो खाते रूस के प्रतिनिधि बैंकों के साथ खोले हैं। कुछ बैंकों ने रूस के सबसे बड़े बैंक एसबेरबैंक और दूसरे सबसे बड़े बैंक वीटीबी बैंक के साथ एसआरवी खाते खोलने की व्यवस्था की है। रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देश जारी होने के बाद अनुमोदन प्राप्त करने वाले ये सबसे पहले बैंक हैं। रूसी बैंक गैझप्रोमबैंक की भारत में कोई शाखा न होने से उसने भी यूको बैंक में एसआरवी खाता खोला है। एसबीआई मॉरीशस लि. और पीपुल्स बैंक ऑफ श्रीलंका ने भारतीय स्टेट बैंक में एसआरवी खाता खोला है। बैंक ऑफ सीलोन ने चेन्नै स्थित अपनी अनुषंगी (subsidiary) में एसआरवी खाता खोला है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने रूस के रॉस बैंक के साथ एक करार किया है। इंडियन बैंक ने श्रीलंका के तीन बैंकों में एसआरवी खाते खोले हैं। इनमें कोलंबो स्थित एनडीबी बैंक और सेलन बैंक शामिल हैं।

प्रारंभिक चरण में भारत के निजी बैंक पश्चिमी जगत द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों से भयभीत होकर एसआरवी खाते खोलने में हिचक रहे थे, किंतु बाद में वे आश्वस्त हो गए कि रूस के साथ व्यवहार करने में नियामकीय जोखिम लगभग नहीं है, क्योंकि रुपये में निपटान की व्यवस्था को रिज़र्व बैंक का समर्थन प्राप्त है। साथ ही, एसआरवी खाते अपनी अधिशेष (surplus) राशि भारत सरकार की प्रतिभूतियों में निवेश कर सकते हैं। यह अभिनव कदम इस व्यवस्था को और लोकप्रिय बनाएगा।

वोस्त्रो खाते खोलने वाले देशों की सूची भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अधिकृत रूप से जारी नहीं की गई है, किंतु वित्त राज्य मंत्री भागवत किशनराव कराड द्वारा 14 मार्च 2023 को राज्यसभा में दिए गए उत्तर के अनुसार रिज़र्व बैंक ने अब तक 60 वोस्त्रो खातों के लिए अनुमोदन दिया है। प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब जैसे मध्य-पूर्व के देशों ने इसमें सहभागिता की रुचि दर्शाई है और इन देशों के केंद्रीय बैंक इस बारे में ब्योरा तैयार कर रहे हैं। भारतीय निर्यात संगठन महासंघ (Federation of Indian Export Organizations or FIEO) के अनुसार रुपये में व्यापार की व्यवस्था से रूस को 5 अरब मिलियन डॉलर के बराबर का अतिरिक्त निर्यात हो सकता है।

निष्कर्ष

अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए रुपये में भुगतान को बढ़ावा देने के भारतीय रिज़र्व बैंक के हाल ही के उपाय निश्चय ही भारतीय रुपये के अंतरराष्ट्रीयकरण का पथ प्रशस्त करेंगे, जिससे वैश्विक व्यापार में भारत की स्थिति मजबूत होगी और भारत की मुद्रा में स्थिरता बनी रहेगी, किंतु रुपये में व्यापार का प्रभाव अंतत: इस बात पर निर्भर होगा कि अपने व्यापारिक भागीदारों के साथ व्यापार में भारत को व्यापार-घाटा हो रहा है या लाभ और कुल द्विपक्षीय व्यापार में से कितना व्यापार रुपये में हो रहा है। प्रारंभिक सफलता के लिए यह भी आवश्यक है कि बड़े व्यापारिक भागीदारों को रुपये में निपटान की संरचना के दायरे में लाया जाए।

References

BIS. (2022). Triennial Central Bank Survey of foreign exchange and Over-the-counter (OTC) derivatives markets in 2022. Bank for International Settlements. Retrieved from https://www.bis.org/statistics/rpfx22.htm

DGFT. (2022). Insertion of Para 2.52(d) under the Foreign Trade Policy in sync with RBI A.P.(DIR Series) Circular No. 10 dated 11th July 2022. Ministry of Commerce & Industry, DGFT. New Delhi: The Directorate General of Foreign Trade (DGFT). Retrieved from https://content.dgft.gov.in/Website/dgftprod/3ae8c6de-dbe5-4430-9b42-11f30d2ea1a9/Notification%2033%20dt%2016-09-22%20Eng-1.pdf

FIEO. (2022). Issues and Challenges in International Trade with focus on India's Exports and its Future Prospects. New Delhi: Federation of Indian Export Organisations. Retrieved from https://www.fieo.org/view_detail.php?lang=0&id=0,21&dcd=8743&did=1663155851qhofq2ol30fl4uksrncfferal3

GoI. (2015). Foreign Trade Policy 2015-2020. New Delhi: Ministry of Commerce and Industry. Retrieved from https://pib.gov.in/PressReleaseIframePage.aspx?PRID=1912572

IMF. (2022). Currency Composition of Official Foreign Exchange Reserves (COFER) December 2022. International Monetary Fund (IMF). Retrieved from https://db.nomics.world/IMF/COFER

RBI. (2016). Foreign Exchange Management (Remittance of Assets) Regulations, 2016. Mumbai: Reserve Bank of India. Retrieved from https://www.rbi.org.in/Scripts/NotificationUser.aspx?Id=10326

RBI. (2022). International Trade Settlement in Indian Rupees (INR). RBI, Foreign Exchange Management. Mumbai: Reserve Bank of India. Retrieved from https://www.rbi.org.in/scripts/FS_Notification.aspx?Id=12358&fn=5&Mode=0